

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 12 सितम्बर, 2017

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य आपदा मोचन निधि से, अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान तथा प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय/सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत कार्यों एवं खोज एवं बचाव उपकरणों के क्रय हेतु तृतीय किस्त के रूप में जिलाधिकारियों के निवर्तन पर धनराशि रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य आपदा मोचन निधि के नवीनतम मानकों के अंतर्गत अहेतुक सहायता, गृह अनुदान, अनुग्रह अनुदान एवं प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत आदि कार्यों एवं खोज एवं बचाव उपकरणों के क्रय हेतु जनपद पिथौरागढ़ हेतु ₹ 5.00 करोड़ एवं अन्य 12 जनपदों हेतु प्रति जनपद ₹ 2.00 करोड़ की दर से कुल ₹ 24.00 करोड़, इस प्रकार संलग्न विवरणानुसार कुल ₹ 29.00 करोड़ (₹ उन्तीस करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर तृतीय किस्त के रूप में रखे जाने एवं निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2— भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं से हुई क्षति में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से व्यय हेतु संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 08.04.2015 में भारत सरकार द्वारा विभागवार तात्कालिक प्रकृति के कार्य स्पष्ट किये गये हैं तथा तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यों में मरम्मत हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी है। अतः प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यों यथा—मार्गों एवं पुलों, पेयजल आपूर्ति से संबन्धित अवसंरचनायें (हैण्ड पम्प, कुंएं, टैंक, क्षतिग्रस्त पाइप लाइन इत्यादि), विद्युत (केवल ऐसे क्षेत्रों जहां तात्कालिक रूप से विद्युत व्यवस्था की जानी होगी), प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, पंचायतों की सामुदायिक परिसम्पत्तियों के मरम्मत हेतु धनराशि व्यय की जायेगी तथा निर्धारित अवधि में ही मरम्मत कार्य पूर्ण किये जायेंगे। भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार आपदा प्रतिवादन के लिये आवश्यक खोज एवं बचाव उपकरण, जिसमें संचार उपकरण भी सम्भिलित है, का क्रय राज्य कार्यकारिणी समिति के आकलन के अनुरूप राज्य आपदा मोचन निधि के कुल वार्षिक आवंटन के 10 प्रतिशत तक तथा क्षमता विकास कार्यक्रमों पर कुल वार्षिक आवंटन के 5 प्रतिशत तक व्यय किये जाने के निर्देश हैं। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3— स्वीकृत की जा रही धनराशि प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान मदों में व्यय की जायेगी। तदोपरान्त विभागीय परिसम्पत्तियों के मरम्मत आदि पर व्यय की जायेगी।

4— आहरण व व्यय केवल उन मरम्मत एवं पुर्नस्थापना कार्यों के लिए किया जायेगा, जो एन.डी.आर.एफ. / एस.डी.आर.एफ. के दिशा-निर्देशों में अनुमन्य हैं।

5— प्रमुख अभियन्ता/विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग के निवर्तन पर क्षतिग्रस्त सड़क एवं पुलों के तात्कालिक मरम्मत एवं पुनर्निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-1808/XVIII-(2)/17-12(4)/2013TC, दिनांक 18 अगस्त, 2017 द्वारा ₹ 25.00 करोड़ की धनराशि निर्गत

की गई है। कृपया उक्त शासनादेश का भी संज्ञान उक्त कार्यों हेतु भी लिया जाना सुनिश्चित करें।

6— स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा।

7— स्वीकृत धनराशि का वितरण तत्परता पूर्वक कराया जायेगा, जिसे प्रभावितों को शीघ्रातिशीघ्र राहत राशि का वितरण सुनिश्चित हो सके।

8— प्रभावितों की सम्यक पहचान एवं पुष्टि के बाद ही स्वीकृत राहत सहायता का वितरण किया जायेगा। राहत सहायता वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता एवं दोहराव की स्थिति पाये जाने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

9— स्वीकृत धनराशि उक्त मद में नियमानुसार व्यय की जायेगी एवं अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

10— व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय—समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

11— स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

12— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-05-राज्य आपदा मोर्चन निधि (90% केन्द्र पोषित)-101-आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण एस.डी.आर.एफ.-02-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

13— यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा०पत्र संख्या-109 मतदेय/वित्त अनु०-५/२०१७, दिनांक 07 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न—यथोक्त।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)

सचिव

संख्या-१७२ (१) / XVIII-(२)/१७-४(१४)/२०१५, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- 1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2— अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 3— अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4— आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
- 5— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 6— अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 7— प्रमुख अभियन्ता/विभागध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- 8— समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9— निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 10— निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 11— प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12— वित्त अनुभाग-५, उत्तराखण्ड शासन।
- 13— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

११६

(सविन बंसल)

अपर सचिव

शासनादेश संख्या-1992 / XVIII-(2)/2017-4(14)/2015, दिनांक/2 सितम्बर, 2017 का
संलग्नक

क्र.सं.	जनपद	स्वीकृत धनराशि (₹ लाख में)
1	पिथौरागढ़	500.00
2	बागेश्वर	200.00
3	अल्मोड़ा	200.00
4	चम्पावत	200.00
5	नैनीताल	200.00
6	उधमसिंहनगर	200.00
7	चमोली	200.00
8	उत्तरकाशी	200.00
9	रुद्रप्रयाग	200.00
10	टिहरी गढ़वाल	200.00
11	पौड़ी गढ़वाल	200.00
12	हरिद्वार	200.00
13	देहरादून।	200.00
	कुल योग	2900.00

(₹ उन्तीस करोड़ मात्र)


(अमित सिंह नेगी)
सचिव